एक-एक घुसपैठिये देश से बाहर होंगे

केन्द्रीय गृह मंत्री बोले- देश को घुसपैठियों से मुक्त कराना सरकार का दृढ़ संकल्प

- गांवों में बेहतर संवाद और संपर्क बनाए रखने पर जोर
- देशविरोधी तत्वों की घुसपैठ रोकी जा सके

पटना, 26 फरवरी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को घुसपैठियों से मुक्त कराना कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का दृढ़ संकल्प है. उन्होंने अररिया में बॉर्डर आउट पोस्ट 'लेटी' और 'इंदरवा' के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि एक-एक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें भारत की भूमि से बाहर किया जाएगा और इस दिशा में ठोस कार्रवाई जल्द शुरू होगी.

शाह ने भारत-नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत 556 किलोमीटर लंबी बॉर्डर रोड के निर्माण का भी उल्लेख किया, जिसमें 14 में से 18 खंडों का कार्य पूरा हो चुका है और शेष चार खंडों में काम तेजी से चल रहा है. उन्होंने कहा कि सड़क परियोजना पूरी होने से सीमा पर निगरानी क्षमता बढ़ेगी और नागरिकों की सुविधाएं भी बेहतर होंगी.

उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की सराहना करते हुए कहा कि मित्र देशों के साथ लगी सीमाओं की सुरक्षा और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना आवश्यक है. गृह मंत्री ने सीमांत गांवों में बेहतर संवाद और संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया ताकि समय पर सटीक सूचनाएं मिल सकें और देशविरोधी तत्वों की घुसपैठ रोकी जा सके.

शाह ने की जनता से सहयोग की अपील की

सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान चलाया जाएगा और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा. अमित शाह ने कहा कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार हैं, और सीमांचल में अभियान जल्द शुरू होगा. उन्होंने घुसपैठियों को केवल चुनाव प्रभावित करने वाला नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा, रोजगार और गरीबों के राशन पर भी प्रतिकूल असर डालने वाला बताया. शाह ने सीमांचल की जनता से सहयोग की अपील की और कहा कि इस अभियान की सफलता में जनभागीदारी अहम होगी.

नागपुर में तीन करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की

मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नागपुर में 3.35 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की है. यह कार्रवाई सचिन शत्रुघ्न पांडे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में की गई है. कुर्क की गई संपत्तियों में तीन व्यावसायिक दुकानें और 10.37 एकड़ क्षेत्रफल के दो भूखंड शामिल हैं.जांच की शुरुआत नागपुर के धंतोली और सीताबल्डी पुलिस थानों में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर हुई थी. आरोप है कि पांडे और उनकी पत्नी खुशी पांडे ने जिन संपत्तियों में उनका कोई अधिकार नहीं था, उन्हें 2.5 करोड़ रुपये में बेचने का समझौता किया और शिकायतकर्ता अमित कोठारी से 2.2 करोड़ रुपये नकद ले लिए. बाद में न तो बिक्री विलेख निष्पादित किया गया और न ही राशि लौटाई गई.

एआई के गलत इस्तेमाल पर रोक जरूरी

- मीडिया व डिजिटल पारिस्थितिकी जरूरी

नई दिल्ली, 26 फरवरी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल समाचार प्रकाशक संघ (डीएनपीए) के सम्मेलन में कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को डीपफेक, गलत जानकारी और साइबर धोखाधड़ी जैसी समस्याओं के मद्देनजर अपनी सामग्री के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी.

उन्होंने मीडिया और डिजिटल पारिस्थितिकी में लोगों का भरोसा बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव भरोसे पर टिकी है. वैष्णव ने चेतावनी दी कि कृत्रिम मीडिया और डिजिटल छेड़छाड़ नागरिकों में भ्रम पैदा कर रही है और वैश्विक स्तर पर संस्थाओं में विश्वास कम कर रही है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना तत्काल आवश्यक है, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा, अश्लील और नकली सामग्री के खिलाफ. डिजिटल मंचों को उपभोक्ताओं को सत्यापित करना चाहिए और गैरकानूनी या हानिकारक गतिविधियों को रोकने में सक्रिय रहना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री ने एआई और सिंथेटिक सामग्री के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की आवश्यकता जताई और कहा कि किसी की सहमति के बिना किसी मशहूर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने टेक कंपनियों से साइबर अपराध और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया.वैष्णव ने राजस्व-साझाकरण और बौद्धिक संपदा के मुद्दों पर भी जोर देते हुए कहा कि सामग्री बनाने वालों को उचित हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि विज्ञान, कला और तकनीकी विकास बाधित न हो. उन्होंने प्लेटफ़ॉर्मों से कहा कि वे ऑनलाइन सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सुधार करें, वरना कई देशों ने कानूनी रूप से हस्तक्षेप किया है.

यूपी और यामानाशी में ग्रीन हाइड्रोजन पर एमओयू

उत्तर प्रदेश ने शासन की कार्यशैली को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाया

टोक्यो, 26 फरवरी. उत्तर प्रदेश सरकार और जापान के यामानाशी प्रांत के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. यह घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के दौरान यामानाशी में आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में की गई.

इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को प्रदेश की इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा.सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने शासन की कार्यशैली को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाया है, जिससे प्रदेश की तेज आर्थिक प्रगति संभव हुई है. उन्होंने बताया कि टोक्यो में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कई जी2जी और जी2बी बैठकें कीं और जापानी उद्योग समूहों से संवाद स्थापित किया. उन्होंने यामानाशी प्रशासन को निवेश संवाद को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया. इसके साथ ही सीएम ने रोबोटिक्स को भविष्य की प्रमुख तकनीक बताते हुए प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की व्यवस्था का उल्लेख किया.

पाक में 5 .6 तीव्रता के भूकंप के झटके

पेशावर. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत के कुछ हिस्सों में बुधवार को 5.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में भारी दहशत फैल गई. इसके साथ ही बाजौर, डायमर शहर और आस-पास के दूसरे इलाकों में भी झटके महसूस किए गए. खैबी पख्तूनख्वा में स्वात और चित्राल इलाकों में कुछ छोटी-मोटी दरारों को छोड़कर किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में जमीन की सतह से 73 किलोमीटर की गहराई पर था.

महाप्रभु की परंपरा सामूहिकता का प्रतीक : मुर्मु

- जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन

रांची, 26 फरवरी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को जमशेदपुर के कदमा (मरीन ड्राइव) में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन किया.

इस अवसर पर उन्होंने 'जय जगन्नाथ' के उद्घोष के साथ कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा पूरी मानवता पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से बरसती है. उन्होंने 'जगन्नाथ के भात, जगत पसारे हाथ' उक्ति का उल्लेख करते हुए बताया कि महाप्रभु की परंपरा सामाजिक समरसता और सामूहिकता का प्रतीक है.

जहां सभी वर्ग एक साथ महाप्रसाद ग्रहण करते हैं.राष्ट्रपति ने कहा कि रथयात्रा में प्रभु जैसे नंदीघोष रथ पर विराजमान होते हैं, उसी प्रकार इस शिलान्यास का समय भी ईश्वरीय संयोग है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह केंद्र सामाजिक जागरण और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त माध्यम बनेगा. झारखंड की पूर्व राज्यपाल रहीं मुर्मु ने जगन्नाथ संस्कृति को जनजातीय और गैर-जनजातीय परंपराओं के समन्वय का प्रतीक बताया तथा सबर राजा विश्वावसु और विद्यापति की कथा का उल्लेख किया.'दारुब्रह्म' स्वरूप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लकड़ी के देवता प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण-सम्मत जीवन शैली का संदेश देते हैं.

ब्राज़ील में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हुई

रियो डी जनेरियो. ब्राज़ील के दक्षिण-पूर्वी मिनास गेरैस राज्य में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गयी है, जबकि 21 लोग अभी भी लापता हैं. प्रशासन की ओर से बुधवार को आये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर जुइज़ डे फोरा में 40 मौतें हुई हैं, जबकि पास की उबा नगरपालिका में छह मौतों की खबर है. अधिकारियों ने बताया कि जुइज़ डे फोरा में 19 और उबा में दो लोग लापता हैं.जुइज़ डे फोरा में लगभग 3,000 लोग और उबा में 26 लोग बेघर हो गये हैं, जबकि भूस्खलन और बाढ़ के खतरे के कारण क्रमशः 400 और 178 लोगों को निकाला गया है.

एक नजर में

अमेरिका नीति बदले तो सुधर सकते हैं संबंध : किम

प्योंगयांग, 26 फरवरी. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि अगर अमेरिका अपनी शत्रुतापूर्ण नीति छोड़कर उत्तर कोरिया को परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर ले, तो दोनों देशों के बीच संबंध सुधारे जा सकते हैं. उन्होंने यह टिप्पणी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की नौवीं कांग्रेस के अवसर पर आयोजित परमाणु सैन्य परेड में की. किम ने कहा कि अमेरिका को उत्तर कोरिया के संविधान में परिभाषित परमाणु स्थिति का सम्मान करना चाहिए और अपनी शत्रुतापूर्ण नीति वापस लेनी चाहिए. तभी उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए तैयार होगा. किम ने कहा कि अमेरिका और उत्तर कोरिया साथ चल सकते हैं, लेकिन केवल तब जब अमेरिका यह स्वीकार करे कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार स्थायी रूप से रहेंगे. उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ किसी भी राजनयिक सुधार की उम्मीद को खारिज करते हुए उन्हें मुख्य शत्रु बताया. किम ने जोर देकर कहा कि पिछले पांच वर्षों में वर्कर्स पार्टी ने देश की पहचान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित की है और विरोधियों को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वैश्विक वातावरण में मौलिक बदलाव नहीं आता, उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा.

अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का तीसरा दौर शुरू

जिनेवा, 26 फरवरी. स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता के तहत ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता का तीसरा दौर गुरुवार को शुरू हो गया. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य जमावड़े के कारण दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है.इससे पहले वार्ता के पहले और दूसरे दौर इस महीने की शुरुआत में मस्कट और जिनेवा में आयोजित किए गए थे. इससे पहले ओमान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री बद्र अल्बुसैदी ने बुधवार शाम जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की. इस बैठक में दोनों मंत्रियों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की.इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उनका देश परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा क्योंकि सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ऐसे हथियारों के विकास प्रतिबंध लगा रखा है. श्री पेजेशकियन ने कहा कि किसी समाज का धार्मिक नेता राजनेताओं की तरह झूठ नहीं बोल सकता और जब उन्होंने घोषणा कर दी है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि हम इसे नहीं बनाएंगे.

असम में 5,067 करोड़ की 35 औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी

- 'रोजगार से पलायन घटेगा: हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, 26 फरवरी. असम सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5,67 करोड़ रुपये की 35 नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी है.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि यह पहल निवेश आकर्षित करने, विकास को तेज करने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से की गई है. उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन से असम में पलायन कम होगा और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा.स्वीकृत इकाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो-प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में होंगी, जिससे बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे. साथ ही, 26 औद्योगिक क्षेत्रों को भी मंजूरी दी गई है, जहां निवेशकों को सुगम बुनियादी ढांचा, भूमि और कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी.

सीएम ने कहा कि औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं और लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय युवाओं में उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने यह भी बताया कि नीति सुधार, बेहतर कानून व्यवस्था और परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी से असम में निवेशकों की रुचि बढ़ी है.राज्य सरकार औद्योगीकरण को विकास की रणनीति का प्रमुख स्तंभ मान रही है, जो सड़क, पुल, बिजली, कौशल विकास और कनेक्टिविटी में चल रहे निवेशों के साथ मेल खाता है.

आज का इतिहास

1594 - हेनरी चतुर्थ फ्रांस का राजा बने.

1700 - विलियम डैम्पियर द्वारा पश्चिमी प्रशांत में नए ब्रिटेन के द्वीप की खोज की गई.

1816 - डचों ने नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस से पुनः सुरीनाम वापस ले लिया.

1829 - तारकी की लड़ाई हुई थी.

1870 - जापान के वर्तमान झंडे को पहली बार जापानी व्यापारी जहाजों के लिए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था.

1874 - पहली बार बेसबॉल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड में खेला गया.

सीबीआई ने धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज किया केस

नई दिल्ली, 26 फरवरी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से 24 फरवरी को रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल अंबानी तथा अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दूसरा मामला दर्ज किया है.

सीबीआई ने गुरुवार को बताया कि यह नया मामला भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के कथित अपराधों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग से संबंधित है.

प्राथमिकी के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा को आरकॉम द्वारा लिए गए ऋणों में 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. आरोप है कि इन ऋणों को संबंधित पक्षों के साथ फर्जी लेनदेन के माध्यम से कहीं और भेजा गया और उनका दुरुपयोग किया गया. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरकॉम के खातों में हेरफेर किया गया और अनियमितताओं को छिपाया गया.

उल्लेखनीय है कि इस ऋण खाते को 2017 में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया था. हालांकि अनिल अंबानी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के आधार पर खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने पर रोक लगा दी गई थी. यह रोक 23 फरवरी, 2026 को हटा दी गई, जिसके बाद बैंक ने शिकायत दर्ज कराई और सीबीआई ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया.

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने इससे पहले 11 बैंकों के समूह के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरकॉम के खिलाफ एक अन्य मामला दर्ज किया था.बैंक ऑफ बड़ौदा उस समूह का हिस्सा नहीं था. वर्तमान मामला आरकॉम द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, तत्कालीन विजया बैंक और तत्कालीन देना बैंक से लिए गए एक अलग ऋण से संबंधित है. विजया बैंक और देना बैंक का अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है.मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने अनिल अंबानी के आवास और आरकॉम के पंजीकृत कार्यालयों पर तलाशी ली.

अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाई अग्रिम जमानत याचिका

लखनऊ. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोपों के बीच गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में शोषण की पुष्टि हुई है, जिससे उनका कानूनी संकट बढ़ गया है. पुलिस ने दोनों बच्चों का मेडिकल कराया और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी. स्वामी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी.

राजनीतिक दलों के खर्च पर रोक की मांग

- केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी

नयी दिल्ली, 26 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की अनियंत्रित खर्च पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया.

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पांचोली की पीठ ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से उनके जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की है. पीठ ने चिंता जताते हुए कहा कि यह मुद्दा कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाता है. गैर-सरकारी संगठन 'कॉमन कॉज' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि अनियंत्रित राजनीतिक खर्च लोकतंत्र को विकृत कर रहा है. उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाले उच्चतम न्यायालय के 2024 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने अनियमित राजनीतिक वित्तपोषण के हानिकारक प्रभाव को स्वीकार किया था. उन्होंने पीठ से कहा कि चुनावों के दौरान बेलगाम धन खर्च की समस्या लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला एक बुनियादी मुद्दा है. न्यायाधीशों ने हालांकि इस पर भी चिंता जताई कि खर्च की सीमा को कैसे लागू किया जा सकता है.

प्रावधान

भारत और नेपाल दोनों ही समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत वाले देश

पर्यावरण संरक्षण को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 26 फरवरी. भारत सरकार और नेपाल सरकार ने वन, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस एमओयू के तहत वन्यजीव कॉरिडोर और आपस में जुड़े क्षेत्रों की बहाली, ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान तथा बेहतर कार्यप्रणाली को साझा करने का प्रावधान है. हस्ताक्षर समारोह नई दिल्ली में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और नेपाल के वन एवं पर्यावरण मंत्री माधव प्रसाद चौलागैन की उपस्थिति में आयोजित किया गया. भारत और नेपाल दोनों ही समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत वाले देश हैं और उनके क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्रों का व्यापक नेटवर्क मौजूद है.

एमओयू में हाथी, गंगा डॉल्फिन, गैंडा, हिम तेंदुआ, बाघ और गिद्ध जैसी प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण, भू-भाग स्तर पर जैव विविधता रणनीतियों का निर्माण, सीमा पार संरक्षण परिदृश्यों और कॉरिडोर की बहाली, वन्यजीव अपराध से मुकाबला, फ्रंट लाइन कर्मचारियों की क्षमता सुदृढ़ करना और जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्मार्ट हरित अवसंरचना को बढ़ावा देना शामिल है. इस समझौता ज्ञापन से भारत-नेपाल वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण में सहयोग मजबूत होगा.

देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बन चुका है सबसे बड़ा अपराध : राहुल गांधी

नयी दिल्ली, 26 फरवरी. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन में शांतिपूर्ण विरोध करना सबसे बड़ा अपराध बन गया है. राहुल ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है, जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साज़िश बताया जाता है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि यदि कोई नागरिक संवैधानिक तरीके से सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसके हिस्से में लाठीचार्ज,

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा

पता- आजाद भवन टाउन हॉल खंडवा, 450001 दूरभाष-0733 2223523

ईमेल- commkhanndwa@mpurban.gov.in

क्रमांक / भण्डार / 202 / 339 खण्डवा दिनांक 10/02/2026

वार्षिक निविदा विज्ञप्ति

संबंधित क्षेत्र के सामग्री प्रदाताओं से निम्नलिखित सामग्री प्रदाय के लिए ई-निविदा प्रकिया में माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है। विस्तृत, कार्य से संबंधित समस्त अर्हताए एवं आवश्यक दस्तावेज www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

क्र.	निविदा क्रमांक	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	अमानत राशि
1	2026_UAD_485330_1	Supply of ISI marked HAVELLS /PANASONIC /WIPRO/BAJAJ/PHILLIPS/ ANCHOR/OREVA SURYA / Crompton / V Guard / Poly cab Company Make Electric Material as per the list provided in BoQ including all duties and Taxes	50 लाख	5000/-	50000/-

निविदा ऑनलाइन क्रय तथा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 27/02/2026 सांय 6 बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की तिथि - 01/04/2026 प्रातः 10 बजे

आयुक्त
नगर पालिक निगम, खण्डवा